## संक्षिप्त समाचार

### शीर्ष छह शहरों में इस साल कार्यालय स्थल की मांग 5-5.5 करोड़ वर्ग फुट रहने की उम्मीद

**नई दिल्ली:** भारत के छह प्रमुख शहरों में कार्यालय स्थल की मांग इस साल अच्छी रहेगी। फिक्की-कोलियर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और विदेशी कंपनियां अपने व्यवसाय विस्तार के लिए 2024 में 5-5.5 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र पट्टे पर ले सकती हैं। छह प्रमुख शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में कार्यालय स्थल का कुल पट्टा 5.82 करोड़ वर्ग फुट था। उद्योग निकाय फिक्की और रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कार्यालय मांग के लिए तीन परिदृश्य दिए गए हैं - आशावादी, यथार्थवादी और निराशावादी। रिपोर्ट के अनुसार यथार्थवादी स्थिति में, इन छह शहरों में इस साल श्रेणी-क के कार्यालय स्थल का कुल पट्टा 5-5.5 करोड़ वर्ग फुट होने का अनुमान है। आशावादी स्थिति में यह आंकड़ा 5.5-6 करोड़ वर्ग फुट तक जा सकता है, जबकि निराशावादी परिदृश्य में यह 4.5-5 करोड़ वर्ग फुट तक गिर सकता है। कोलियर्स इंडिया के कार्यालय सेवाओं के प्रमुख अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि भारत में कार्यालय स्थान की मांग 2024 में लगातार तीसरी बार पांच करोड़ वर्ग फुट से अधिक रहने का अनुमान है।

### 1 पर 2 बोनस शेयर देगी यह कंपनी, होली से पहले रिकॉर्ड डेट

**नईदिल्ली, एजेंसी।** खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी एमके प्रोटीन्स ने शेयरधारकों के लिए बोनस इक्विटी शेयर की घोषणा की है। कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 इक्विटी के लिए इलिजिबल निवेशकों को 1 इक्विटी आवंटित की जाएगी। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है। बता दें कि कोई भी कंपनी अपने शेयरधारकों को एक निश्चित रेशियो में अतिरिक्त बोनस शेयर देती है, ताकि बाजार में लिक्विडिटी बढ़े और कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का एक हिस्सा शेयरधारकों के बीच विभाजित किया जा सके। कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों के हकदार शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 15 मार्च, 2024 तय की है। बीएसई पर एमके प्रोटीन्स के शेयर की मौजूदा कीमत 45.02 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 563.21 करोड़ रुपये है। शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम और निचला स्तर क्रमशः 100 रुपये और 35.07 रुपये है।

### स्टॉक मार्केट इस हफ्ते कैसा करेगा प्रदर्शन, ये बातें तय करेंगी दिशा

**नईदिल्ली, एजेंसी।** स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक रुझानों से तय होगी। सप्ताह के दौरान घरेलू मोर्चे पर औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) और मुद्रास्फीति के आंकड़े आने हैं। विश्लेषको ने यह राय जताई है। विश्लेषकों का कहना है कि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से बाजार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुए थे।

# भारती एयरटेल ने चार दिन में कमाए 38,726 करोड़

## इन्फोसिस, रिलायंस और एलआईसी को नुकसान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पिछले हफ्ते शेयर बाजार में केवल चार दिन कारोबार हुआ। महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार को शेयर बाजार में छुट्टी रही। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 74,119.39 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। उसी दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 22,493.55 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स की टॉप 10 मूल्यवान कंपनियों में से सात के मार्केट कैप में कुल मिलाकर 71,301.34 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। कम कारोबारी सत्रों के सप्ताह के दौरान सबसे अधिक लाभ में भारती एयरटेल रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज , एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के बाजार मूल्यांकन में बढ़ोतरी हुई, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम की बाजार

हैसियत घट गई। सप्ताह के दौरान देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 38,726.67 करोड़ रुपये बढ़कर 6,77,448.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एसबीआई के बाजार पूंजीकरण में 13,476.16 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 7,03,393.29 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 12,243.35 करोड़ रुपये बढ़कर 10,98,707.88 करोड़ रुपये पर और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 3,099.76 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 7,63,581.30 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 1,469.81 करोड़ रुपये बढ़कर 5,15,921.57 करोड़ रुपये और टीसीएस का मूल्यांकन 1,157.79 करोड़ रुपये बढ़कर 14,87,070.15 करोड़ रुपये रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 1,127.8 करोड़ रुपये बढ़कर 5,68,753.81 करोड़ रुपये हो गया।

### रिलायंस में गिरावट

इस रुख के उलट देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 15,875.81 करोड़ रुपये घटकर 6,71,121.34 करोड़ रुपये पर आ गया। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 15,391.94 करोड़ रुपये घटकर 20,01,358.50 करोड़ रुपये रह गई। एलआईसी के मूल्यांकन में 6,166.87 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 6,48,596.89 करोड़ रुपये रह गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमशः टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एलआईसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

# भारत और ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता, वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ाने पर जोर

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना लगभग 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के परिणामों का प्रतीक है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा, उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी कम या खत्म कर देते हैं। गौरतलब है कि भारत और ईएफटीए जनवरी 2008 से समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) कहा जाता है। दोनों पक्षों ने अक्तूबर 2023 में बातचीत फिर से शुरू की और इसे जल्द से जल्द खत्म किया। बता दें ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को

बढ़ावा देने और तीव्र करने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन राज्यों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। भारत 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ अलग से एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

### स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

भारत ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए वार्ता में तेजी लाने या तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। भारत-ईएफटीए दोतरफा व्यापार 2022-23 में 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में 27.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में व्यापार घाटा 14.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और उसके बाद नॉर्वे का स्थान है।

### युवाओं के विकास और रोजगार पर जोर- पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई पहलुओं में संरचनात्मक विविधताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के पूरक है। व्यापार और निवेश के अवसरों के खुलने के साथ हम विश्वास और महत्वाकांक्षा के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं।

# निष्पक्ष व्यापार के लिए साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक, व्यापार समझौते पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता खुले, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

भारत और ईएफटीए के बीच हुआ व्यापारिक समझौते के दिन को खास बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और फार्मा जैसे कई क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में ईएफटीए देशों का वैश्विक नेतृत्व सहयोग के नए दरवाजे खोलेगा। पीएम मोदी ने अपने लिखित संदेश में कहा कि भारत-ईएफटीए व्यापार और

आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करने में शामिल वार्ताकारों और हस्ताक्षरकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री का संदेश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईएफटीए देशों के मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, भारत की अर्थव्यवस्था ने एक लंबी छलांग लगाई है, जो दुनिया की ग्यारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारा अगला लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाना है। बता दें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

### क्या है ईएफटीए

दोनों पक्षों ने अक्तूबर 2023 में बातचीत फिर से शुरू की और इसे जल्द से जल्द खत्म किया। बता दें ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन राज्यों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। हालांकि भारत 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ अलग से एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

# ब्रिक्स सीसीआई वी के चौथे वार्षिक शिखर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर किया गया

**नई दिल्ली, एजेंसी।** - भारत की अध्यक्षता में हुए जी-20 सम्मेलन में महिलाओं की अगुवाई में विकास पर ज़ोर और समावेशी और सकारात्मक परिवर्तन को गति देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के साथ ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स सीसीआई वी ने चौथे वार्षिक शिखर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह की मेजबानी की जिसका विषय था- ब्रिक्स सीसीआई वी ने ब्रिक्स के नए युगः महिला सशक्तिकरण के लिए टेक

एवं बिजनेस में क्षितिज नाम से एक रिपोर्ट का भी अनावरण जिसमें सभी ब्रिक्स देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता परिदृश्य पर खास ज़ोर है। इसने ब्रिक्स सीसीआई वी ग्लोबल वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम की महिला प्रतिभागियों के प्रथम बैच के दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया।

इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, क्यूबा, कोस्टा रिका, चिली, बेलारूस, जांबिया, अंगोला, चाद, कोमोरोस, वेनेजुएला सहित अन्य देशों से राजनयिक शामिल हुए। पद्म विभूषण से सम्मानित राज्यसभा सदस्य डाक्टर सोनल मानसिंह इस शिखर सम्मेलन की मुख्य अतिथि थीं। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री शाजिया इल्मी, उत्तर प्रदेश की पूर्व महिला एवं बाल कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री स्वाति सिंह, पूर्व ब्रिक्स शेरपा और भारत सरकार के सचिव (सेवानिवृत्त) संजय भट्टाचार्य और विशेष पुलिस आयुक्त (महिला एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई के प्रभारी) श्री अजय चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया।

# आईपीओ से पहले स्विगी की वैल्युएशन बढ़ी, 13% बढ़त के बाद पार किया 12 बिलियन का आंकड़ा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** अमेरिका की एसेट मैनेजर बैरन कैपिटल ग्रुप ने आईपीओ-बाउंड फूड-डिलीवरी ऐप स्विगी के फेयर वैल्यू में वृद्धि की है, जिसके बाद 2022 में इसका मूल्यांकन 10.7 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन से 13त्न बढ़कर 12.16 बिलियन डॉलर हो गया है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की फाइलिंग में इसकी जानकारी मिली है। अमेरिका स्थित एसेट मैनेजर ने पहले जनवरी 2022 में 700 मिलियन डॉलर के फंडिंग राउंड के दौरान स्विगी में निवेश किया था।

31 दिसंबर तक, एसेट मैनेजर के फंड के पास स्विगी की मूल कंपनी बंडल टेक्नोलॉजीज में 87.2 मिलियन की हिस्सेदारी थी, जो 74.4 मिलियन से 17त्न अधिक थी। 2022 में, स्विगी ने इनवेस्को के नेतृत्व में अपने सीरीज़ च राउंड में 700 मिलियन जुटाए।

इस दौर में इसका मूल्यांकन दोगुना होकर 10.7 बिलियन डॉलर हो गया। 2023 में जुलाई-सितंबर तिमाही में इनवेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन बढ़ाकर 7.85 अरब डॉलर कर दिया।

एक अलग फाइलिंग में, बैरन कैपिटल ने कहा कि स्विगी भारतीय फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में लगभग 45त्न बाजार हिस्सेदारी रखती है। बेंगलूरु की यह कंपनी इसी साल शेयर बाजार में कदम रखना चाहती है और आईपीओ के जरिये 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दरख्वास्त डालेगी। कंपनी का इरादा आईपीओ में 10-11 अरब डॉलर का मूल्यांकन हासिल करने का है।

स्विगी ने आईपीओ की योजना पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मगर मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले चरणों में जुटाई गई रकम में से कंपनी के पास तकरीबन 80 करोड़ डॉलर की नकदी रखी हुई है। आईपीओ से पहले स्विगी ने मुनाफे में आने की कोशिशें भी बढ़ा दी हैं। आईपीओ से पहले ज्यादा दुरुस्त बनने के लिए स्विगी 350 से 400 कर्मचारियों की छंटनी के बारे में भी सोच रही है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या करीब 6,000 है।

पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 45 फीसदी बढ़कर 8,625 करोड़ रुपए हो गया था। मगर उसका शुद्ध घाटा भी बढ़कर 4,179 करोड़ रुपए तक चला गया था। उससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में कंपनी का राजस्व 5,705 करोड़ रुपए और शुद्ध घाटा 3,629 करोड़ रुपए था।

# दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग को दिए निर्देश, आईजीएसटी पर 6 प्रतिशत रिफंड करें रिटर्न

**नई दिल्ली, एजेंसी।** दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग को लंबित आईजीएसटी रिफंड पर 6प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा है कि सीजीएसटी/डीजीएसटी अधिनियम की धारा 56 विलंबित रिफंड पर ब्याज से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत लौटाए जाने वाले किसी भी कर को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो ऐसे रिफंड के संबंध में 6त्न की दर से ब्याज देय होगा। आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर की वापसी की तारीख तक 60 दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने दुबई को मोबाइल फोन और एसेसरीज का निर्यात किया था। सामान्य तौर पर रिफंड का दावा शिपिंग बिलों के माध्यम से किया जाता था, जो समय-समय पर दायर किए गए शिपिंग बिलों को संसाधित करने के बाद सीमा शुल्क द्वारा जारी किया जाता था। दिसंबर 2022 के दौरान करोड़ से अधिक रुपयों का निर्यात किया था। इसके अलावा, फरवरी 2023 में करीब तीन करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। जिस पर 50

लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसी तरह मार्च 2023 के महीने में रुपये का निर्यात हुआ। 95,90,489 बने, जिस पर आईजीएसटी रु. 17,26,288 का भुगतान किया गया और मई 2023 के महीने के लिए आईजीएसटी का बोझ उतारकर मोबाइल और उनके सामान का निर्यात किया गया। अदालत ने माना कि यदि रिफंड के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने पर भी दावा की गई राशि वापस नहीं की जाती है, तो धारा 56 के तहत ब्याज देय हो जाता है। धारा 56 के तहत ब्याज का भुगतान, वैधानिक होने के कारण, बिना किसी दावे के स्वचालित रूप से देय है, यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर धन वापसी नहीं की जाती है। ब्याज का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे पर निर्भर नहीं करता है और इसलिए फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-01 में ब्याज के दावे की छूट के आधार पर इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ब्याज अनुदान के भुगतान का प्रश्न तभी उठता है जब आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिफंड नहीं दिया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर रिफंड के भुगतान में देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार, भले ही याचिकाकर्ता ने अपने रिफंड आवेदन में ब्याज का दावा नहीं किया हो, लेकिन उसके ब्याज के दावे को धारा 56 के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और स्वचालित रूप से देय है। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता रिफंड आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होकर उस तारीख तक 6त्न की दर से वैधानिक ब्याज का हकदार है ।